MINISTÈRE
DE L'EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
ET DE LA MODERNISATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sous-direction de la Formation et des Concours

Bureau des concours et examens professionnels
RH4B

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L'ACCÈS A L'EMPLOI DE SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE D'ORIENT) AU TITRE DE L'ANNÉE 2021

ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

Jeudi 24 septembre 2020

HINDI

Durée totale de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 2
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Barème de notation : composition en hindi 12 points ; traduction en français 8 points

COMPOSITION EN HINDI

Composition en hindi à partir d'une question, rédigée dans cette même langue, liée à l'actualité.
(***350 mots avec une tolérance de plus ou moins 10%)***

SUJET :

भारत में असंगिठत क्षेत्र का क्या महत्त्व है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हिस्सा है तथा इसके क्या मज़बूत और क्या कमज़ोर पहलू हैं?

MINISTÈRE
DE L'EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
ET DE LA MODERNISATION

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sous-direction de la Formation et des Concours

Bureau des concours et examens professionnels
RH4B

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L'ACCÈS A L'EMPLOI DE SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE D'ORIENT) AU TITRE DE L'ANNÉE 2021

ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

Jeudi 24 septembre 2020

HINDI

Durée totale de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 2

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Barème de notation : composition en hindi 12 points ; traduction en français 8 points

TRADUCTION EN FRANÇAIS

Traduction en français d'un texte rédigé en hindi.

TEXTE AU VERSO

BBC Hindi - 16 juin 2020

कोरोना ने सेहत के मामले में सरकारी कंजूसी की पोल खोली है?

सलमान रावी, बीबीसी संवाददाता

कोरोना महामारी के बीच लोगों के टेस्ट न हो पाने, स्वास्थ्यकर्मियों को उपयुक्त पीपीई किट (Personal Protection Equipment kit) न मिल पाने, और उन्हें वेतन तक न दिए जाने की ख़बरों ने भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के संकट को एक बार फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है.

वैसे भारत में सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है जहाँ डॉक्टरों, बिस्तरों, सुविधाओं और दवाइयों की कमी एक आम बात है, बदइन्तज़ामी की समस्या ऊपर से है, और यह हालत दो-चार साल पुरानी नहीं, बल्कि शुरू से ही ऐसी है.

इस बदहाली की मुख्य वजह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की कमी. हालाँकि पिछले सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी बजट में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हुई है और यह २०१६-१७ के तक़रीबन ३७ हज़ार करोड़ से बढ़कर अब ६५ हज़ार करोड़ से ऊपर जा चुका है लेकिन यह अभी भी भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से भी कम है.

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि २०१३-१४ में यह आँकड़ा १.१५ प्रतिशत था, जो अब १.८ प्रतिशत हो गया है. उन्होंने सदन को पिछले साल दिए गए लिखित जवाब में कहा था कि सरकार के पास फ़िलहाल यही आँकड़े मौजूद हैं.

जीडीपी का दो प्रतिशत भी स्वास्थ्य पर नहीं

स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपनी तरफ़ से ख़र्च करती हैं और ऊपर दिए आँकड़े सिर्फ़ केंद्र सरकार के ख़र्च के हैं, हाल के दिनों में भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी कंपनियों का दख़ल भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है मगर वहाँ मिलने वाली सुविधाओं के चार्ज इतने अधिक हैं कि वे भारत की बड़ी जनसंख्या की पहुँच से बाहर हैं.

पाँच विकासशील देशों के समूह - ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ़्रीका) में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ख़र्च करने वालों में भारत सबसे निचले पायदान पर है. जहाँ ब्राज़ील अपने कुल जीडीपी का ९.२ प्रतिशत इस क्षेत्र में लगाता है, वहीं चीन, जिससे भारत की बार-बार तुलना की जाती है, का आँकड़ा पाँच फ़ीसद है, जो भारत के ढाई गुने से भी अधिक है.

भारत में स्वास्थ्य पर ख़र्च हमेशा से ही जीडीपी के दो प्रतिशत के नीचे ही रहा है चाहे जिसकी भी सरकार रही हो जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसे पाँच के आस-पास होना चाहिए. आँकड़े बताते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकारों के दो कार्यकालों की तुलना में स्वास्थ्य पर ज़्यादा ख़र्च किया है.

[../..]